Page Three
Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

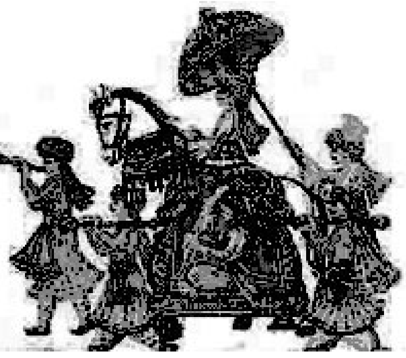

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

महामारी के सच को छिपाने का काम कर रही है राज्य सरकार

कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह हुए हमलावर

आरोप

■ किसी भी प्रकार के संवाद से बच रही राज्य सरकार

संवाददाता

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी के सच को छिपाने का काम कर रही है जिसके कारण वह किसी भी प्रकार के संवाद से बच रही है। वहीं केन्द्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज चीन और नेपाल भारत को आंखें दिखा रहे है और 56 इंच का सीना चुप्प है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर कोरोना के मामले में हठधर्मिता दिखाते हुए संवाद से बचने का आरोप लगाया है। चर्चा अब इस बात को लेकर तेज हो रही है क्या वाकई सरकार सच को छुपा रही है जिसके चलते वह संवाद से बचना चाहती है?

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार

से लगातार कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए ठोस पहल किये जाने की मांग लगातार की जा रही है लेकिन प्रदेश सरकार पिंजरे में कैद होकर रह गई है कि कहीं कोरोना उन पर न आ जाये। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार कोरोना महामारी फैल रही है जिसको लेकर कांग्रेस ने लगातार प्रदेश सरकार से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन प्रदेश सरकार हठधर्मिता के चलते किसी से भी कोई संवाद नही करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य सरकार से क्वारंटाइन सेन्टरों की दशा सही करने व कारोना जांच बढ़ाये जाने की मांग की लेकिन अभी तक कोरोना वायरस की जांचे नहीं बढाई गयी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन 77 दिनों में मात्र 39 हजार लोगों की कोरोना जांचे हुई है जिनमें दो हजार जांचें प्राइवेट लैब से हुई है,यह प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना टेस्ट लैब नहीं बना पाई है कुमायूं में केवल हल्द्वानी में ही जांचें हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि प्रदेश में कोरोना जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाये, कम से कम हर जिले में एक जांच केंद्र स्थापित किया जाय। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है और अभी यह पैकेज जनता की समझ से बाहर है, सरकार इसका सही इस्तेमाल करती तो आज लोग भूख से नही मरती, इस 20 लाख करोड़ में एक भी रुपया जनता के खातों में नही आया। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट नही कर पायी है, सरकार को भी लग रहा है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं है इसलिए उन्होंने निर्णय चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर छोड़ दिया है।

गैरसैण ग्रीष्मकालीन राजधानी पर उन्होंने कहा कि भाजपा राजधानी मुद्दे पर राजनीति कर रही है, प्रदेश में एक अस्थायी राजधानी है और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो प्रदेश की स्थायी राजधानी कहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद से सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी अभी तक गैरसैण नही गया है।

न्यूज डायरी

चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना के एएन–32 विमान की सफल लैंडिंग

संवाददाता उत्तरकाशी। चीन सीमा पर बढ़ी तनातनी के बाद से देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेनाओं की सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरकाशी जिले की चिन्यालीसौड़ पट्टी पर बुधवार को वायुसेना के एनएन–32 मालवाहक विमान की सफल लैंडिंग हुई। विमान का चिन्यालीसौड़ में टेक ऑफ और लैंडिंग का सिलसिला जारी है। ये विमान आगरा एयर बेस से चिन्यालीसौड़ हवाईपट्टी पहुंचा। बता दें कि चिन्यालीसौड़ से चीन सीमा की दूरी 125 किमी है। चीन सीमा पर तनातनी की खबर के बाद से ही वायु सेना अभ्यास में जुटी हुई है। दरअसल, लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद उपजे तनाव के बीच चीन से सटी उत्तराखंड की 345 किलोमीटर सीमा हमेशा से संवदेनशील रही है।

गैरसैंण बनाई जाये प्रदेश की स्थाई राजधानीः महिला मंच

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड महिला मंच ने राज्य सरकार द्वारा गैरसैंण भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की अधिसूचना का विरोध करते हुए राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने घरों में रहकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का काम किया और कहा कि प्रदेश की स्थाई राजधानी गैरसैंण के अलावा कहीं भी स्वीकार नहीं की जायेगी। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में महिला मंच से जुड़ी हुई कार्यकर्तायें अपने अपने घरों में प्रदेश की स्थाई राजधानी गैरसैंण बनाये जाने की मांग को लेकर धरने पर रही ओर वहां पर गैरसैंण भराडीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाये जाने का विरोध किया।

गोदरेज प्रोफेशनल ने लॉकडाऊन के बाद सैलून सुरक्षा कार्यक्रम की घोषणा कीं

संवाददाता देहरादून। गोदरेज प्रोफेशनल, हेयर कलर, केयर, स्टाइलिंग और केराटिन उत्पादों के साथ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल) की प्रोफेशंल ब्रांड ने सैलून सुरक्षा कार्यक्रम की घोषणा देहरादून और अन्य शहरों में की है. ये घोषणा भारतीय सैलून उद्योग को पोस्ट कोरोना दौर में काम करने में समर्थन करेगा. इंडस्ट्री के पहले प्रोफेशन ब्यूटी ब्रांड पहल के रूप में, गोदरेज प्रोफेशनल द्वारा सैलून सुरक्षा कार्यक्रम के तीन स्तंभ हैं. जैसे, सैलून के लिए मुफ्त और रियायती सैनिटाइजर और डिस्पोजेबल किट का वितरण, सैलून बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए सुरक्षा और स्वच्छता पर शिक्षाऔर बैक–टू–बिजनेस समर्थन. ये सभी पहलें देहरादून के उन सभी सैलून के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है और यह सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है, जो गोदरेज प्रोफेशनल का उपयोग करते हैं।

केंद्र अधिवक्ताओं के हितो लिए जारी करे कल्याणकारी योजना

संवाददाता देहरादून। अधिवक्ता शिवा वर्मा ने कहा है कि अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ,हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट के अधिवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर एक साइनिंग पेटिशन अभियान छेड़ा है इसके लिए एडवोकेट वेलफेयर ग्रुप बनाया गया है। जिसमें देशभर के 16 अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि अधिवक्ताओं के हितों के लिए कल्याणकारी योजनायें जारी किये जाने की आवश्यकता है। दून से अधिवक्ता शिवा वर्मा भी इस ग्रुप में शामिल है।

अधिवक्ता शिवा वर्मा ने बताया कि 23 मार्च से देशभर में लोग डाउन चल रहा है इस दौरान अदालतों में सिर्फ जरूरी काम किया जा रहा है ऐसे में कई अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ग्रुप की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक ज्ञापन भेजकर जल्द ही मांग की जाएगी कि केंद्रीय सरकार कोई ठोस योजना बनाये।

सौ हॉकरों को वितरित की राशन किट

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने जनता को सुबह सुबह समाचार पत्र पहुंचाने वाले लगभग सौ हॉकरों को राशन की किट वितरित की। इस अवसर पर हॉकरों ने कांग्रेस का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस संकट की घडी में सरकार के बजाय कांग्रेस ने उनके दर्द को जाना। ईसी रोड स्थित मंगला देवी इंटर कालेज में देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत दून न्यूज पेपर हॉकर यूनियन के सौ सदस्यों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने संयुक्त रूप से राशन किट वितरित की। प्रीतम सिंह ने कहा है कि आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी फैली हुई है और इससे हमारा राज्य उत्तराखंड भी अछूता नहीं है।

डामरीकरण की बाट जो रही है शहीद के नाम से बनी सड़क

■ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन

■भारी वाहनों की आवाजाही न होने से बागवानों को दिक्कतें

संवाददाता

पुरोला। मोरी विकासखण्ड के बंगाण क्षेत्र के गमरी आराकोट के कारगिल शहीद दिनेश रावत के सम्मान में बनी गमरी,भुटाणु,मैजणी और किरोली मोटर मार्ग को बने दस वर्ष होने के बाद भी डामरीकरण न होने से सड़क बेहाल है ग्रामीणों ने विभागों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी पुरोला मनीष कुमार के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।

ज्ञापन मे बताया गया है कि सड़क की हालात इस कदर है कि क्षेत्र के बागवानों को टेक्सियों से सेब,मटर, आलू आदि ढुलान कर त्यूणी–आराकोट मुख्य मोटर मार्ग तक पहुंचा। वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चन्द खण्डूरी के कार्यकाल में 20 किमी0 शहीद दिनेश रावत मोटर मार्ग के लिए पाँच करोड की वितीय सवीकधति की गई थी, मोटर मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग पुरोला को सौपी गयी जिस पर विभाग ने 2007 में प्रथम चरण की निविदाएं लगवाई तथा 2012–13 मे मोटर मार्ग के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया लेकिन तब से आज तक यह मोटर मार्ग जस के तस पड़ा है इसके डामरीकरण न होने से सड़क आरटीओ पास भी नही हो पायी जिस कारण सेब,नासपाती,आड़ू,प्लम की बागवानी के साथ–साथ मटर, आलू आदि फसलो के लिए क्षेत्र के ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के बागवान और समाजसेवी मनमोहन चौहान,रघुवीर सिंह, कुंदन सिंह,कल्याण सिंह,प्रेम सिंह आदि ने बताया कि लोक निर्माण विभाग पुरोला ने तीन बार मोटर मार्ग डामरीकरण की डीपीआर शासन को भेजी लेकिन शासन ने तीनों बार इसे निरस्त कर दिया।

वर्ष 2018 में तत्कालीन क्षेत्र पंचायत सदस्य भुटाणु केवला चौहान ने डामरीकरण के लिए सड़क को पीएमजीएसवाई को कार्यदायी संस्था बनाने की मांग की लेकिन मोटर मार्ग में अभी तक कुछ काम नही किया गया।

व्यापारियों ने की बिजली,पानी बिल माफ करनें की मांग

संवाददाता पुरोला। यमुना घाटी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधियों की बुधवार को पुरोला में हुई बैठक में सरकार से लाकडाउन के समय का बिजली व पानी बिल माफ करने की मांग की गई है। बुधवार को यमुना घाटी के पुरोला, नौगांव, मोरी व बडकोट के प्रांतीय उधोगव्यापार मंडल प्रतिनिधियों की बैठक में व्यापारियों के हितों को लेकर हुई बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में जहां सरकार से लाकडाउन अवधी का बिजली व पानी का बिल माफ करनें की मांग की गई वहीं गुरूवार अर्थात 11 जून से व्यापारिक व प्रतिष्ठान जो अभी तक प्रातःआठ से 2 बजे तक खुलते थे अब प्रातः 7 बजे से चार बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रस्ताव पास कर सरकार से सभी व्यापारियों का सरकारी बीमा करानें समेत लाक डाउन के चलते बीते तीन माह से चोपट होटल ढाबा,रेस्टोरेंट मालिकों को 6 माह का आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई।